गुढ़ में बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता परेशान

नवभारत न्यूज

गुढ़, 27 जून, गुढ़ नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है.

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि गुढ़ में बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बताया जा रहा है कि कई बार हल्की बारिश या मामूली हवा चलने पर भी बिजली काट दी जाती है, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि मौसम पूरी तरह सामान्य होने के बावजूद घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है. शनिवार को भी तेज धूप और सामान्य मौसम के बीच दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लगातार अकारण 3 घंटे तक बिजली बंद रही, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विभाग को किसी कारणवश बिजली आपूर्ति बंद करनी होती है तो इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए, ताकि लोग अपनी आवश्यक तैयारियां कर सकें. बिना सूचना के बार-बार बिजली कटौती होने से व्यापारियों, विद्यार्थियों और घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है. नागरिकों ने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि बिजली कटौती की स्थिति में समय रहते सूचना जारी की जाए तथा अनावश्यक कटौती पर रोक लगाई जाए. लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के दौर में लगातार बिजली बाधित रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. अब देखना यह होगा कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जनता की इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं.

ग्राम पंचायत पटेहरा में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया

नशे से दूर रहने का लिया संकल्प, नशा मुक्त समाज का हो निर्माण

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 27 जून, कलेक्टर संजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिले में संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेहरा में चौपाल के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सुरक्षित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा.

कार्यक्रम के दौरान 'नशा मुक्त भारत, विकसित भारत की पहचान' विषय पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया. साथ ही 17 जून से 26 जून तक संचालित नशा मुक्त भारत सप्ताह के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को नशा न करने तथा अपने परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई. कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के अजय पटेल (सुरक्षा अधिकारी) सहित उमेश रावत एवं बीनू यादव ने सहभागिता करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों से अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया.

हर दुकान पर दो डस्टबिन अनिवार्य

मऊगंज, कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नगर परिषद मऊगंज क्षेत्र का भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बाहर गीले एवं सूखे कचरे के लिए पृथक-पृथक डस्टबिन नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा नगर परिषद के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी व्यापारी एवं नागरिक अपनी दुकानों एवं मकानों के सामने गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है.

सातवीं बार प्रदेश कार्यसमिति में शामिल हुए अखंड प्रताप सिंह

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 27 जून, भाजपा द्वारा वरिष्ठ नेता अखंड प्रताप सिंह को पुनः प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किए जाने पर मऊगंज जिले में खुशी का माहौल है.

कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की है. अखंड प्रताप सिंह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं. प्रदेश कार्यसमिति में पुनः शामिल किए जाने की सूचना मिलते ही मऊगंज जिले में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया. जिसमें राजेंद्र मिश्रा भाजपा जिलाध्यक्ष मऊगंज अमित सिंह मंडल अध्यक्ष मऊगंज, मनोज सिंह कोषाध्यक्ष, प्रभात सिंह, सुशील सोनी, राजकुमार मिश्रा, विपिन मिश्रा, वंश बहादुर सिंह, राजेश गुप्ता, शिव बहादुर सिंह लोढ़ी, मनोज गुप्ता खटखरी, बृजलाल कोल, भारत पांडेय, विनोद सिंह अतरैला, वंश गोपाल तिवारी शामिल है.

शिक्षकों की क्रमोन्नति सूची तत्काल जारी हो : प्रान्ताध्यक्ष

नवभारत न्यूज

मऊगंज, 27 जून, शिक्षक संवर्ग को 35 वर्ष की सेवा पश्चात चतुर्थ क्रमोन्नति (समयमान वेतनमान) देने का शासन ने प्रावधान किया है, किन्तु प्रदेश के 80 प्रतिशत जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने क्रमोन्नति सूची जारी नहीं किये हैं.

जिससे शिक्षकों में आक्रोस व्याप्त है. सर्व शिक्षक संघ के प्रान्ताध्यक्ष सतानन्द मिश्र ने कहा है कि, शिक्षक हित के कार्य में प्रायः अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जाती है, जो उचित नहीं है. अभी भी 80 प्रतिशत जिलों की क्रमोन्नति सूची पेंडिंग है.

रीवा मऊगंज जिले की सूची बनने के बाद नहीं निकल पा रही है, प्रान्ताध्यक्ष ने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का ध्यान शिक्षक हितैषी कार्यों को तत्काल पूर्ण करने की ओर आकृष्ट किया है.

बेश कीमती खनिज के अवैध परिवहन का कारोबार

नवभारत न्यूज

गुढ़, 27 जून, दिलीप बिल्डिकॉन प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा विगत कई महीनों से बदवार सीतापुर मुख्य सड़क मार्ग के किनारे पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जो अवैध खनिज माफियायों के लिए लिए किसी सोने की खदान मिल जाने जैसा प्रतीत हो रहा है.

बता दें कि बदवार से सीतापुर तक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सम्बंधित कम्पनी को पाइप डालने के लिए उच्च दाब की ब्लास्टिंग करनी पड़ती है जिसके कारण काफी ज्यादा मात्रा मे पत्थर निकलते हैं जो इन अवैध कारोबारियों की बिना लागत तिजोरी भरने के काम आ रही हैं. हद तो तब हो गई जब सम्बंधित कम्पनी की जेसीबी से ही लोडिंग कर ट्रैक्टर के माध्यम से पत्थर ढुलाई का कार्य किया जाने लगा जिससे इस सम्पूर्ण अवैध खनिज परिवहन एवं संचयन में सम्बंधित कम्पनी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है, जो कि स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग की कार्यशैली मे बड़ा प्रश्न चिन्ह है.

सुरक्षा मापदंडों में हो रही लापरवाही को रोका जाए

नवभारत न्यूज

चाकघाट, 27 जून, लखनऊ में हुए लाइब्रेरी अग्निकांड से एक बार फिर निजी लाइब्रेरी में सुरक्षा की पोल खुल गई.

निजी लाइब्रेरी एवं निजी कोचिंग संस्थान संचालकों के लिए भारी भरकम आय के स्रोत बनते जा रहे हैं, जिसके चलते कोचिंग सेंटर के संचालक अथवा लाइब्रेरी संचालक सुरक्षा मानकों का खुलेआम अनदेखा कर कर रहे हैं और धड़ाधड़ संस्थान खोले जा रहे हैं. रीवा जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों एवं कस्बायी क्षेत्र में जो लोग कोचिंग एवं लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं वे अध्यनरत बच्चों की सुरक्षा मापदंड को खुले आम अवहेलना कर रहे हैं. रीवा जिले के आंचल में खुल रहे कोचिंग या लाइब्रेरी भवन में छात्रों के प्रवेश के लिए मुख्य दरवाजे के साथ कम से कम दो अतिरिक्त दरवाजे भी होने चाहिए. जिससे दुर्घटना के समय अन्य दरवाजा से भी छात्र बाहर निकाल कर अपनी जान बचा सके. अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निरोधक है यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए. पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. इस मामले में शासन को ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए कि पुस्तकालय एवं कोचिंग का कार्य बहु मंजिली भवन में बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए. भूतल एवं प्रथम तल में ही यह संस्थान संचालित किया जाना चाहिए.

शहरों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में भी चलाए जा रहे इन कोचिंग एवं लाइब्रेरी संस्थाओं मैं सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच होनी चाहिए. तथा सुरक्षा मापदंडों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी होनी चाहिए.

गुढ़ में एक घंटे की बारिश ने खोली नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल

नवभारत न्यूज

गुढ़, 27 जून, गुढ़ नगर परिषद क्षेत्र में शुक्रवार को हुई महज एक घंटे की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी. वार्ड क्रमांक 13 में यूनियन बैंक के सामने नाली की सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर पानी भर गया.

जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की नियमित सफाई कराई जाती, तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होती. बारिश के बाद सड़क पर जलभराव होने से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों ने चिंता जताई कि यदि इसी तरह की बारिश बैंक के कार्यकाल के दौरान हो जाए, तो यूनियन बैंक परिसर तक पानी पहुंच सकता है, जिससे बैंकिंग कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी. ऐसे में ग्राहकों और कर्मचारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. केवल वार्ड क्रमांक 13 ही नहीं, बल्कि सब्जी मंडी क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 10 सहित नगर के कई स्थानों पर पानी भरने की समस्या देखने को मिली. थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव की स्थिति बनना नगर परिषद की तैयारियों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद से मांग की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए नालियों की तत्काल सफाई कराई जाए तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके. समय रहते व्यवस्था नही बनाई गई तो स्थित खराब होगी. अब देखना यह होगा कि गुढ़ नगर परिषद इस समस्या को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाती है या फिर नागरिकों को इसी तरह जलभराव की परेशानी झेलनी पड़ेगी.

रीता मिश्रा को मिली पीएचडी की उपाधि

नवभारत न्यूज

गुढ़, 27 जून, रीता मिश्रा को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा प्राणीशास्त्र (जूलॉजी) विषय में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है. यह शोधकार्य मॉडल साइंस कॉलेज, रीवा में प्रोफेसर डॉ. आरती सक्सेना के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ.

इस उपलब्धि पर शोध-निर्देशक प्रोफेसर डॉ. आरती सक्सेना ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रीता मिश्रा को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं. वहीं मॉडल साइंस कॉलेज, रीवा के समस्त प्राध्यापकगण ने भी उनकी इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए शोध एवं शैक्षणिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की कामना की.

रीता मिश्रा ने अपनी शोध-थीसिस स्वर्गीय डॉ. बी. पी. गर्ग को समर्पित करते हुए इस सफलता का श्रेय उनके आशीर्वाद एवं प्रेरणा को दिया. साथ ही उन्होंने प्रोफेसर डॉ. अरविंद उपाध्याय द्वारा प्रत्येक चरण में मिले सहयोग एवं मार्गदर्शन के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर उनकी माता श्रीमती देववती मिश्रा, पिता जवाहर लाल मिश्रा, बड़ी बहन श्रीमती गीता गर्ग एवं सीता उपाध्याय, सास श्रीमती लक्ष्मीबाई त्रिपाठी, ससुर अरुणेंद्र त्रिपाठी तथा पति वरुणेंद्र त्रिपाठी सहित बी. एन. त्रिपाठी, एडी एस. के. त्रिपाठी, प्राचार्य डॉ. सीमा शुक्ला ने खुशी व्यक्ति की है.

पल्स पोलियो अभियान आज से 30 तक

3 .56 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

नवभारत न्यूज

सतना 27 जून। जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 3 लाख 56 हजार 767 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने बच्चों के अभिभावकों से टीका करण बूथ पर बच्चों को दवा पिलाने की अपील की हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि जिले में 2826 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 74 ट्रांजिट बूथ एवं 46 मोबाइल बूथ बनाए गए हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 2966 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 5932 कार्यकर्ता और 295 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अभियान के पहले दिन 28 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य दल घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगे।

अभियान के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य आवागमन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले बच्चों को भी खुराक दी जा सके। वहीं झुग्गी-बस्तियों और ईंट भट्टों के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो पहले दिन से ही घर-घर जाकर दवा पिलाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 0-5 वर्ष के सभी बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं और अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

सीएम डॉ . मोहन यादव ने 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि दी

नवभारत न्यूज

सतना 27 जून। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 जून को बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि साल 2027 को राज्य सरकार श्युवा वर्षश् के रूप में मनाएगी। दूसरी ओर, श्ग्लोबल इंवेस्टर्स समिटश् (ळैै) भी जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी।

सीएम डॉ. यादव ने ये घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2026 पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित श्सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिटश् में कीं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सफल उद्यमियों की विकास गाथा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से 760 से अधिक ईकाइयों को प्रोत्सान राशि दी। उन्होंने प्रदेश के 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ की सहायता राशि भी दी। मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र और लोन स्वीकृति पत्र दिए गए। देवास, पांढुर्ना, टीकमगढ़, उज्जैन को एमएसएमई भवन की सौगात मिली। मंदसौर में मुल्तानपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 288 भू-खंड, मंडला में 165 भू-खंड, जबलपुर में 61 भू-खंड, बैतूल में 50 भू-खंड, कटनी के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 68 भू-खंड, नीमच के सरगना औद्योगिक क्षेत्र में 127 भू-खंड, खरगोन के डाबरिया औद्योगिक क्षेत्र में 103 भू-खंड दिए गए। प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएसएमई विभाग के बीच स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू भी साइन किए गए। समिट में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कटनी और मंडला के उद्यमियों से संवाद भी किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 41 हजार से अधिक एमएसएमई यूनिट्स की कमान माताओं-बहनों के हाथों में है। गत वर्षों के मुकाबले वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व 59 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 16 कलस्टर का निर्माण किया है और 14 नए कलस्टर पर काम चल रहा है। राज्य को ओडीओपी में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश के 20 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं। राज्य सरकार सभी की कठिनाई को समझते हुए विकास की धारा में सरलता, सुचिता और अपने पारदर्शी निर्णयों के बूते आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) को भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पूरे वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर को आधुनिक तरीके से नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को लोन चुकाने के लिए नई सौगात दी है। किसान जिस तारीख को लोन लेंगे, उसके 12 माह की अवधि में लोन भर सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च की बाध्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी। सरकार गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 को गरीब कल्याण, वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में कार्य किया।

आज पिलाई जाएगी पोलियो की दवा

मैहर 27 जून। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत मैहर जिले में 28 जून 30 जून तक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।

अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर मैहर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं।

मंजूरी के 13 वर्ष बाद से क्यों लटक रही है रीवा-मिर्जापुर रेल लाइन

नवभारत न्यूज

हनुमना, 27 जून, विंध्य क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण रेल लाइन, जो देश की आजादी के जमाने से लंबित है, और जिसके निर्माण की मांग काफी लंबे अर्से से की जा रही है, ताकि रीवा मिर्जापुर जिले का काफी बड़ा भू-भाग जो रेल लाइन सुविधा से वंचित हैं उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके, और लोगों को आवागमन के साथ-साथ रोजी रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके.

परंतु उक्त रेल लाइन के लिए जिम्मेदार दोनों जिले के वर्तमान जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण डबल इंजन की सरकार में भी रीवा मिर्जापुर जैसे अति महत्वपूर्ण रेल लाइन निर्माण की प्रक्रिया आगे न बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश के ही दो-तीन जिले जहां की नई रेलवे अभी हाल के वर्षों में मंजूर हुई, और वहां के जन प्रतिनिधियों की सक्रियता से निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई,

परंतु इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमें रीवा क्षेत्र के जिम्मेदार प्रतिनिधि के साथ-साथ पड़ोसी जिले के भी जनप्रतिनिधि इस तरह मिले हैं, हद तो तब हो गई जब रीवा संसदीय क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सांसद जनार्दन मिश्रा उक्त रेल लाइन के मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों पर बार-बार भड़क जाते हैं, और बे फालतू और ऊल-जुलूल जवाब देने लगते हैं, और बताते हैं कि देश 1952 से स्वतंत्र हुआ है, और कितने सांसद हुए कितने बार हुए तब जाकर सीधी सिंगरौली रेल लाइन का काम शुरू हुआ, अभी हमें तो दो-तीन बार ही सांसद बने हुआ, यानी उन्हें अभी उक्त रेल लाइन निर्माण कराने के लिए 10 बार सांसद बनाना पड़ेगा, और एक बात नई जानकारी हुई कि देश 1952 में स्वतंत्र हुआ था, दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं संगठन को स्तीफा ले लेना चाहिए, और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से किसी योग्य प्रत्याशी के नाम पर विचार करना चाहिए, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में योग्य एवं कर्मठ नेताओं की कमी नहीं है, विदित हो कि उक्त महत्वपूर्ण रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया आगे न बढ़ने से जनता में काफी आक्रोश है, जिसका ठीकरा लोग रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी पर फोड़ रहे हैं, लोग यह तक पूछ रहे हैं कि जब एक आर्थिक व्यापारिक जन सुविधा के दृष्टि से जबलपुर मंडल द्वारा प्रथम सर्वे किया जा चुका था तब दूसरा सर्वे प्रयागराज रेल मंडल द्वारा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी ,और किसके इशारे पर किया गया, जिसका खुलासा किया जाए, एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विगत 3 वर्ष पूर्व केवड़िया गुजरात रेलवे स्टेशन के उद्घाटन अवसर पर भाषण दिए थे, कि अब हमारी सरकार में रेलवे के प्रोजेक्ट लटकते नहीं,तब फिर मंजूरी के 13 वर्ष बाद से क्यों लटक रही है.